

शारीरिक दंड

प्रासंगिकता: जीएस 2: केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए कल्याण

किशोर न्याय अधिनियम, शारीरिक दंड, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, मानसिक उत्पीड़न, भारतीय दंड संहिता, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अनुच्छेद 21ए, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 39 (ई), शारीरिक दंड निगरानी प्रकोष्ठ।

संदर्भ:

- पुणे में तीन निजी स्कूलों के शिक्षकों के खिलाफ 10 वीं कक्षा के तीन छात्रों की कथित रूप से पिटाई करने और आंतरिक मूल्यांकन में उन्हें खराब ग्रेड देने की धमकी देने के लिए किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। कानूनी प्रावधानों पर एक नज़र जो शारीरिक दंड को रोकती है, और जिनके पास दुर्व्यवहार के खिलाफ बच्चों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है।



शारीरिक दंड क्या है?

- शारीरिक दंड बच्चों के खिलाफ हिंसा का सबसे व्यापक रूप है।
- यह कोई भी सजा है जिसमें शारीरिक बल का उपयोग किया जाता है और कुछ हद तक दर्द या असुविधा पैदा करने का इरादा होता है।
- यह मानव गरिमा और शारीरिक अखंडता के लिए सम्मान करने के लिए बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है।
- भारत में बच्चों को लक्षित करने वाली 'शारीरिक दंड' की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है, लेकिन निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 धारा 17 (1) के तहत 'शारीरिक दंड' और 'मानसिक उत्पीड़न' को प्रतिबंधित करता है और इसे धारा 17 (2) के तहत दंडनीय अपराध बनाता है।
- शारीरिक दंड को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक है।
- शारीरिक दंड:**
 - एनसीपीसीआर के अनुसार, शारीरिक दंड को किसी भी कार्यवाई के रूप में समझा जाता है जो एक बच्चे को दर्द, चोट /

चोट और असुविधा का कारण बनता है।

- इसमें बच्चों को एक असहज स्थिति (बेंच पर खड़े होना, कुर्सी जैसी स्थिति में दीवार के खिलाफ खड़े होना, सिर पर स्कूल बैग के साथ खड़े होना, पैरों के माध्यम से कान पकड़ना, घुटने टेकना, किसी भी चीज का जबरन अंतर्ग्रहण, कक्षा, पुस्तकालय, शौचालय या स्कूल में किसी भी बंद स्थान में निरोध) शामिल है।
- **मानसिक उत्पीड़न:**
 - इसे किसी भी गैर-शारीरिक उपचार के रूप में समझा जाता है जो बच्चे के शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए हानिकारक है।
 - इसमें व्यंग्य, नामों को बुलाना और अपमानजनक विशेषणों का उपयोग करके डांटना, धमकी देना, बच्चे के लिए अपमानजनक टिप्पणियों का उपयोग करना, बच्चे का उपहास करना या अपमानित करना, बच्चे को शर्मिंदा करना और बहुत कुछ शामिल है।

ऐसी सजा के खिलाफ कानून के तहत क्या प्रावधान हैं?

- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009:**
 - शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17, शारीरिक दंड पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है।
 - यह ऐसे व्यक्ति पर लागू सेवा नियमों के अनुसार दोषी व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्धारित करता है।
 - 2009 के आरटीई अधिनियम की धारा 8 और 9 में उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण पर यह कर्तव्य लगाया गया है कि "यह सुनिश्चित करें कि कमजोर वर्ग से संबंधित बच्चे और वंचित समूह से संबंधित बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाए और किसी भी आधार पर प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त करने और पूरा करने से रोका न जाए।"
- **किशोर न्याय अधिनियम:**
 - किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 23 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो एक किशोर के नियंत्रण में है और जो किशोर को छोड़ देता है, हमला करता है, बेनकाब करता है या जानबूझकर उपेक्षा करता है या उसे छोड़ने, हमला करने, उजागर करने या उपेक्षित करने के लिए खरीदता है, जो बदले में उसे मानसिक या शारीरिक दर्द का कारण बनता है, उसे छह महीने तक के कारावास से दंडित किया जाएगा, या दंड दिया जाएगा, या दोनों हो सकता है।
 - किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 बच्चों के साथ क्रूरता के लिए सजा निर्धारित करती है।
- **भारतीय दंड संहिता**
 - भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधान हैं, जो शारीरिक दंड के अपराधियों को दिए गए नुकसान की गंभीरता के आधार पर नियंत्रित करते हैं। इसमें शामिल हैं
 - एक बच्चे द्वारा की गई आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित धारा 305
 - धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित
 - धारा 325 जो स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के बारे में है
- **शारीरिक दंड को रोकने के लिए स्थापित निकाय-**

- दो प्रमुख सांविधिक निकाय, जो शारीरिक दंड के उन्मूलन के लिए शीर्ष पर हैं, वे हैं
 - राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
 - बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग
- इन निकायों को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि बच्चों के साथ निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुरूप व्यवहार किया जा रहा है।

भारत में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 21 ए: 6-14 आयु वर्ग में अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान
- अनुच्छेद 24: यह 14 साल की उम्र तक खतरनाक काम में बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है।
- अनुच्छेद 39 (ई): यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि आर्थिक असमानता के कारण निविदा आयु के बच्चों का दुरुपयोग न हो।
- अनुच्छेद 45: यह राज्य का कर्तव्य है कि वह 0-6 आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल के लिए प्रदान करे।
- अनुच्छेद 51ए (के): माता-पिता का मौलिक कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि उनका बच्चा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए शिक्षा प्राप्त करे।

शारीरिक दंड के परिणाम:

- एक शोध में पाया गया कि शारीरिक दंड बच्चों के लिए किसी भी सकारात्मक परिणाम से जुड़ा नहीं था और बच्चों को गंभीर हिंसा या उपेक्षा का अनुभव करने के जोखिम में वृद्धि हुई थी।
- शारीरिक दंड से जुड़े नकारात्मक परिणाम, जैसे कि व्यवहार संबंधी समस्याएं, बच्चे के लिंग, जाति या जातीयता के बावजूद और देखभाल करने वालों की समग्र शिक्षण शैलियों की परवाह किए बिना हुई।
- बच्चों के लिए नकारात्मक परिणामों का परिमाण शारीरिक दंड की आवृत्ति के साथ बढ़ गया।
- शारीरिक दंड बच्चों के व्यवहार में सुधार नहीं करता है और इसके बजाय इसे बदतर बनाता है।

शारीरिक दंड के पीछे कुछ कारण:

- शिक्षक हिंसा और दुर्व्यवहार के अलावा अन्य विकल्पों का पता लगाने के लिए जागरूकता या रुचि की सामान्य कमी के कारण शारीरिक दंड (या मानसिक उत्पीड़न) का उपयोग करते हैं।
- शिक्षक भावनाओं से प्रभावित होने पर बच्चों के खिलाफ हिंसा करते हैं। कहते हैं, जब वे कक्षा का प्रबंधन करने में असमर्थ होने पर निराश महसूस करते हैं।
- कम वेतनमान, एक विषम छात्र-शिक्षक अनुपात और खराब संसाधन वाले स्कूलों जैसे अन्य कारक भावनात्मक निर्माण-अप में योगदान करते हैं।
- शिक्षक जब धैर्य खो देते हैं तो छात्रों पर हमला करते हैं और शारीरिक दंड पैटर्न को अपनाते हैं।

एनसीपीसीआर के दिशानिर्देश शारीरिक दंड को समाप्त करने के बारे में क्या कहते हैं?

- एनसीपीसीआर दिशानिर्देशों के तहत, प्रत्येक स्कूल को छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक तंत्र विकसित करने

और स्पष्ट प्रोटोकॉल तैयार करने की आवश्यकता होती है।

- ड्रॉप बॉक्स को रखा जाना है जहां पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत छोड़ सकता है और गोपनीयता की रक्षा के लिए गुमनामी बनाए रखी जा सकती है।
- प्रत्येक स्कूल को एक 'शारीरिक दंड निगरानी प्रकोष्ठ' का गठन करना होता है जिसमें दो शिक्षक, दो माता-पिता, एक डॉक्टर, एक वकील (डीएलएसए द्वारा नामित), काउंसलर, उस क्षेत्र के एक स्वतंत्र बाल अधिकार कार्यकर्ता और उस स्कूल के दो वरिष्ठ छात्र शामिल होते हैं।
- यह CPMC शारीरिक दंड की शिकायतों की जांच करेगा।

न्यायपालिका द्वारा दिखाई गई चिंता

- एस जय सिंह और अन्य बनाम राज्य और अन्य, 2018
 - यह मामला एक छात्र से संबंधित है जो स्कूल में देर से पहुंचने के लिए "डकवॉक" (शारीरिक दंड का एक रूप) करने के बाद मर गया था।
 - न्यायमूर्ति वेंकटेश ने कहा कि सजा के ऐसे रूपों के खिलाफ कानून के बावजूद, ये घटनाएं अभी भी देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में प्रचलित हैं।
 - उन्होंने कहा, "यहां तक कि जानवरों को क्रूरता के खिलाफ संरक्षित किया जाता है ... हमारे बच्चे निश्चित रूप से जानवरों से भी बदतर नहीं हो सकते हैं।"
 - न्यायपालिका का रवैया शारीरिक दंड की गहरी जड़ों वाली समस्या के प्रति भी अस्पष्ट है।

आगे की राह

- भारत सरकार ने पूरे देश में शारीरिक दंड की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, कानून और बाल अधिकार संधियों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का कार्यान्वयन स्कूल और छात्र स्तर पर लागू नहीं किया जाता है।
- शारीरिक दंड और कक्षा हिंसा का अभ्यास मौजूद है। कई विकासशील देशों ने लोगों की सदियों पुरानी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए एजेंडा को अपनाया है कि शारीरिक दंड केवल बुरे सामाजिक व्यवहार या कार्रवाई को रोक सकते हैं। भारत को बाल अधिकारों की रक्षा करनी थी और शारीरिक दंड के खिलाफ जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देना था।

स्रोत:

<https://indianexpress.com/article/explained/explained-what-the-law-says-on-protecting-children-against-corporal-punishment-8063964/>

प्रीलिमस परीक्षा प्रश्न -

Q. शारीरिक दंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. शारीरिक दंड कोई भी सजा है जिसमें शारीरिक बल का उपयोग किया जाता है और कुछ हद तक दर्द या असुविधा पैदा करने का इरादा होता है।
2. भारतीय कानून में बच्चों को लक्षित करने वाली 'शारीरिक दंड' की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है।
3. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 केवल शारीरिक दंड को निषिद्ध करता है न कि मानसिक उत्पीड़ना।

नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनें:

- a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) इन सभी

उत्तर: a

व्याख्या:

- शारीरिक दंड बच्चों के खिलाफ हिंसा का सबसे व्यापक रूप है।
- यह कोई भी सजा है जिसमें शारीरिक बल का उपयोग किया जाता है और कुछ हद तक दर्द या असुविधा पैदा करने का इरादा होता है।
- यह मानव गरिमा और शारीरिक अखंडता के लिए सम्मान करने के लिए बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है।
- हालांकि भारतीय कानून में बच्चों को लक्षित करने वाली 'शारीरिक दंड' की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है, मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 धारा 17 (1) के तहत 'शारीरिक दंड' और 'मानसिक उत्पीड़न' को प्रतिबंधित करता है और इसे धारा 17 (2) के तहत एक दंडनीय अपराध बनाता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न -

Q. शारीरिक दंड क्या है? भारत में शारीरिक दंड के खिलाफ विभिन्न कानूनों के तहत प्रावधानों पर चर्चा करें।

